Grant of subsidy to small industries in North-Eastern Region

1337. DR. NAGEN SAIKIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) how many small industries in the North-Eastern Region of the country have been given subsidy grants by the Central Government;

(b) what is the total amount of grant released so far;

(c) whether the Central Government have decided to discontinue the subsidy in such small scale industries in Assam;

(d) if so, what is the reason therefor; and

(e) whether such a subsidy has been discontinued to similar industries in other States also?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) A total amount of Rs. 47.97 tonnes has been reimbursed to North Eastern Region as Central Investment Subsidy since 1971 and upto 31.10.1988. Information about the number of small industries given subsidy is not maintained centrally.

(c) to (e) The Government is yet to take a decision on the continuation of the capital incentive subsidy schemes which was valid till 30.9.1988.

राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए योजना

1338. **डॉ० अबरार अहमद खान**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा देश के औद्योगिक विकास के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इसमें से राजस्थान राज्य के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए कोई विशेष योजना बनाई है अथवा केन्द्रीय सरकार शीघ्र ही राजस्थान में कोई नया बडा उद्योग स्थापित करेगी, यदि हां, तो ऐसे उद्योगों तथा स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण की नीति के अनुसार राजस्थान के उद्योग विहीन जिलों के संबंध में केन्द्रीय सरकार का रवैया क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मार्च, 1986 के अंत तक सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के उपक्रमों में किया गया कुल सकल मूल्य (ग्रॉस ब्लाक) के रूप में 68051.87 करोड रूपए था, जिसमें से राजस्थान में किए गए निवेश की मात्रा 780.95 करोड रूपए थे ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस बात पर बल दिया है कि नए एकक स्थापित करने के बजाए पुनर्गठन में सुधार, उत्पादकता में सुधार, तकनोलोजी का अभ्यायुत्थान और विद्यमान एककों का आधुनिकीकरण करके विद्यमान सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया जाए । सातवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की जिन महत्वपूर्ण चालू औद्योगिक परियोजनाओं के लिए परिव्यय का प्रावधान किया गया हैं उनकी एक सूची विवरण में दी गई है । [नीचे देखिये]

(ग) दिनांक 31-10-1988 तक राजस्थान को केन्द्रीय निवेश राजसहायता के रूप में कुल 60.72 करोड़ रुपए की राशि प्रतिपूरित की गयी हैं । इसके अतिरिक्त अधिसूचित उद्योग रहित जिलों, सिरोही, जैसलमेर, चुरू और बाडमेर के चुने हुए विकास केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु राजस्थान को 191.41 लाख रुपए की राशि और दी गयी है